jay bihar Amit.qxd 08/14/2014 5:57 PM Page 1

हिन्दुस्तान

पटना LIVE

बुधवार, 13 अगस्त, 2014, पटना

www.livehindustan.com

पटना लाइव

सांस्कृतिक कार्यक्रमों से स्वच्छ पर्यावरण का दिया संदेश, मनाया आजादी का उत्सव

पटनानामा

स्वतंत्रता की राष्ट्रीय आकांक्षा को स्वर देनेवालों में अग्रणी थे दिनकर जी

एंटरटेनमेंट

45 मिनट की परफॉर्मेंस के लिए लाखों रुपए की डिमांड करने लगे हैं योयो हनी सिंह

एनएच किनारे 600 मकान टूटेंगे

हिन्दुस्तान लाइव
पड़ताल

- अनीसाबाद से बख्तियारपुर तक हो रहा है फोरलेन का निर्माण
- एनएच एक्ट के अनुसार बिल्डिंग लाइन में नही बन सकते मकान
- सर्विस रोड की अनुमति नहीं लेने वाले भी हैं सूची में शामिल

10 मीटर तक सड़क के बाद होती है बिल्डिंग लाइन

15 मीटर तक बिल्डिंग लाइन के बाद होती है कंट्रोल लाइन

50 किमी लंबा है बख्तियारपुर - अनीसाबाद फोरलेन

पटना | रंजीत सिंह

पटना में बाइपास किनारे बने छह सौ मकानों के टूटने का खतरा है। ये बिल्डिंग लाइन के अंदर आ रहे हैं। नेशनल हाइवे एक्ट के अनुसार यहां कोई निर्माण नहीं कराया जाना चाहिए। मगर यहां मकान और दुकान बना दिए गए हैं। स्कूल और अस्पताल खुल गए हैं। नेशनल हाइवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इन मकानों की सूची तैयार कर ली है। जल्द ही इन्हें नोटिस भेजी जाएगी।

एनएचएआई पटना के अनीसाबाद से बख्तियारपुर तक फोर लेन का निर्माण कर रहा है। बाइपास इसका हिस्सा होगा। इसके लिए सड़क चौड़ीकरण की जरूरत पड़ेगी। मगर एनएचएआई के सामने दिक्कत यह है कि सड़क किनारे मकान और दुकान बन गए हैं। लाइव टीम की पड़ताल में पता चला कि बिल्डिंग लाइन के अंदर कई अस्पताल और स्कूल भी चल रहे हैं। लोगों ने घर बनाकर अपने हिसाब से रास्ता भी निकाल लिया है। कई लोगों ने नाले पर बांस लगाकर तो कई ने पुल बनाकर रास्ता बनाया है। कुछ लोगों ने बाइपास किनारे नाले को पूरी तरह पाटकर आने-जाने की व्यवस्था कर ली है। इसके कारण सड़क किनारे जहां-तहां जलजमाव भी हो रहा है। यह भी नेशनल हाइवे के लिए एक खतरा है क्योंकि सड़क टूटने लगेगी। एनएचएआई अधिकारियों का कहना है कि जरूरत पड़ने पर अतिक्रमण हटाया जाएगा।

प्रशासन को अवगत कराया

सड़क किनारे दुकानें खुल जाने से जगह-जगह ट्रक सहित अन्य वाहन हमेशा खड़े रहते हैं। एनएचएआई ने जिला प्रशासन और नगर निगम को इससे अवगत करा दिया है। एनएचएआई का कहना है कि सड़क विस्तार में दिक्कत हो रही है।

रामकृष्णा नगर के पास राष्ट्रीय राजमार्ग के किनारे बने मकान। इनमें से कई निर्माण एनएच एक्ट के अनुसार बिल्डिंग लाइन के अंदर आ रहे हैं। इनकी सूची बनाई जा चुकी है। सड़क विस्तार में बिल्डिंग लाइन के अंदर के मकान तोड़े जा सकते हैं। ● फोटो एसकेपी

लोगों ने बिना अनुमति लिए संपर्क पथ भी बना लिए है, ऐसे मकानों और दुकानों की सूची भी एनएचएआई ने तैयार कर ली है।

पहले क्या कर रहा था एनएचएआई

सवाल यह है कि एनएचएआई ने तब क्यों नहीं निर्माण रोका जब दुकान या मकान बन रहे थे। इतने सारे मकान एक दिन में तो नहीं बन गए? आम लोगों को एनएच एक्ट की जानकारी भी नहीं होती। इसलिए यह एनएचएआई के लिए जरूरी था कि वह लोगों को एक्ट की जानकारी देता।

संपर्क पथ की अनुमति है जरूरी

एनएच एक्ट के अनुसार सड़क (आरओ डब्ल्यू) के बाद दस मीटर तक बिल्डिंग लाइन होती है। इसमें निर्माण पर पूरी तरह रोक है। उसके बाद पंद्रह मीटर तक कंट्रोल लाइन होती है। इसमें केवल अस्थायी निर्माण हो सकता है। यदि बिल्डिंग लाइन में कोई निर्माण कराता है तो एनएचएआई की अनुमति लेनी होती है। सर्विस रोड और ड्रेनेज सिस्टम होने पर ही एनएचएआई निर्माण और संपर्क पथ की अनुमति देता है।

तैयार की गई है मकानों की सूची

एनएचएआई ने ऐसे मकान की लिस्ट बनाई है, जिन्होंने बिल्डिंग लाइन के अंदर स्थायी, अस्थायी मकान या दुकान बना लिए हैं। कुछ लोगों ने बिना एनएचएआई की अनुमति के संपर्क पथ निकाल लिया है। यह गलत है।

-वीबी सिंह, प्रोजेक्ट मैनेजर, एनएचएआई

पहले सड़क बनी या मकान बने थे

एनएचएआई की थ्योरी यह है कि पहले सड़क बनी या मकान। इसी थ्योरी के आधार पर अनीसाबाद से बख्तियारपुर तक बन रहे फोरलेन के किनारे भी अतिक्रमण को रोका जा रहा है। एनएचएआई का मानना है कि करीब पचास किमी लंबी सड़क के किनारे अभी कोई निर्माण नहीं हुआ है। भविष्य में यदि कोई यहां निर्माण कराना चाहता है तो पहले उसे सर्विस रोड और ड्रेनेज सिस्टम बनाना होगा। उसके बाद अनुमति लेनी होगी।

स्वतंत्रता दिवस पर दिखेगी ट्रैफिक पुलिस की झांकी

पटना | कार्यालय संवाददाता

स्वतंत्रता दिवस पर गांधी मैदान में निकलने वाली झांकियों को अंतिम रूप दे दिया गया है। इस बार कुल 11 झांकियां निकलेंगी। पटनावासियों को जागरूक करने के लिए पटना पुलिस भी झांकी निकालेगी। थीम होगा पटना ट्रैफिक पुलिस। इसके साथ ही अन्य 10 विभागों की भी झांकियां निकलेगी। डीएम मनीष कुमार वर्मा ने बताया कि सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए जा रहे हैं।

उन्होंने बताया कि सभी विभाग अलग-अलग झांकी निकालेंगे। इसमें कला, संस्कृति एवं युवा विभाग की तरफ से एकलव्य आवासीय प्रशिक्षण केंद्र, बिहार शिक्षा परियोजना परिषद की बालिका शिक्षा थीम पर आधारित झांकी रहेगी। सूचना एवं जनसंपर्क विभाग की तरफ से तख्त श्रीहरमंदिरजी पटना साहिब और पर्यटन निदेशालय की तरफ से मंदार पर्वत की झांकी निकाली जाएगी। कृषि विभाग की तरफ से राज्य में कृषि शिक्षा, उद्योग विभाग की तरफ से हस्तशिल्प को प्रोत्साहित करने के लिए राज्य सरकार द्वारा उठाए जा रहे कदम, समेकित बाल विकास सेवाएं निदेशालय की तरफ से बाल कुपोषण मुक्त बिहार, सहकारिता की ओर से वैज्ञानिक भंडारण गैसीफायर, सहकारी बैंकों का आधुनिकीकरण थीम पर झांकी निकाली जाएगी।

तैयारी

- राजधानी में इस बार कुल 11 झांकियां निकाली जाएंगी
- जिलाधिकारी ने कहा, किए जा रहे सुरक्षा के कड़े इंतजाम

छात्रवृत्ति मिलने में इस साल भी होगा विलंब

पटना | कार्यालय संवाददाता

तकनीकी छात्रों को सत्र 2014-15 की छात्रवृत्ति मिलने में देरी होगी। छात्रवृत्ति में गड़बड़ी पकड़े जाने के बाद इस बार सख्ती से आवेदनों की जांच की जा रही है। हालांकि जिला कल्याण अधिकारी ने दावा किया है कि आवेदनों की जांच का काम अगस्त में पूरा कर लिया जाएगा।

जिले के छह हजार छात्रों ने छात्रवृत्ति के लिए आवेदन किया है। सत्र 2014-15 की छात्रवृत्ति के लिए ऑनलाइन आवेदन मंगाए गए थे। पटना जिले के आवेदन प्राप्त हो गए हैं। इसकी जांच चल रही है। शुरुआत में ही कॉलेजों का फर्जीवाड़ा पकड़ में आने के बाद जांच में सख्ती बरती जा रही है। जिला कल्याण अधिकारी पवन मिश्रा ने बताया कि एक-एक आवेदन की जांच की जा रही है। यदि किसी आवेदन में कोई कमी या फिर कोई शक होता है तो उसे छांट दिया जा रहा है। सभी आवेदनों की जांच अगस्त माह में पूरी कर ली जाए ताकि समय से छात्रों को छात्रवृत्ति मिल सके।

पिछले सत्र में छात्रवृत्ति के खाते से फर्जीवाड़ा कर करीब 86 लाख रुपए निकाले गए थे। फिर सभी खातों के संचालन पर रोक लगी थी। इस कारण काफी छात्रों को छात्रवृत्ति नहीं मिल पाई थी। अभी भी ऐसे कई छात्र हैं जो कल्याण विभाग का चक्कर काट रहे हैं।

आवेदनों की जांच

- छात्रवृत्ति आवेदनों की सख्ती से की जा रही हैं जांच
- पिछले वर्ष करीब 86 लाख रुपए का हुआ था फर्जीवाड़ा

कोई है...

यह तस्वीर राजेंद्र स्मारक चिकित्सा विज्ञान अनुसंधान (आरएमआरआई) के इनडोर वार्ड की है। यहां के अधिकतर बेड फट चुके हैं। भर्ती मरीजों को अस्पताल की ओर से चादर तक नहीं मिलती। अस्पताल स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय भारत सरकार की ओर से संचालित है। कोई है जो मरीजों को मिलने वाली सुविधाओं की सुधि ले। ● रविशंकर सिंह

पीएमसीएच में दो दशक में नहीं खुल सकी किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट

पटना | वरीय संवाददाता

विश्व अंगदान दिवस पर विशेष

राज्य के अस्पतालों में अंगदान और प्रत्यारोपण करना संभव नहीं है। इसके लिए आवश्यक आधारभूत संरचना का निर्माण अब तक राजधानी के अस्पतालों में नहीं हो सका है। पीएमसीएच में किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट और नेत्र बैंक कागज में ही चल रहे हैं। हालांकि किडनी प्रत्यारोपण कमेटी के सदस्य प्रो. हेमंत कुमार का कहना है कि जल्द ही पीएमसीएच और आईजीआईएमएस में प्रत्यारोपण की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी, ताकि उन्हें बाहर न जाना पड़े।

डॉक्टर हैं नियुक्त

पीएमसीएच में किडनी ट्रांसप्लांट करने वाले विशेषज्ञ डॉक्टर मौजूद हैं लेकिन आवश्यक संसाधनों मसलन उपकरण, विशेषज्ञों और माड्यूलर ओटी के अभाव में यूनिट शुरू नहीं हो सकी। अस्पताल प्रबंधन यह बता पाने में असमर्थ है कि कब तक प्रत्यारोपण के लिए आधारभूत संरचना तैयार हो सकेगी। किडनी ट्रांसप्लांट यूनिट के डॉ. अशोक कुमार सिंह बताते हैं कि पिछले दो दशकों से ज्यादा समय बीत जाने के बाद भी यूनिट चालू नहीं हो सकी। इस बात को डॉ. अशोक कुमार पहले भी कई मंचों पर उठा चुके हैं लेकिन अब तक इस दिशा में खास पहल नहीं हो सकी है।

टिश्यू टैपिंग की समस्या

ट्रांसप्लांट के लिए किडनी देने और किडनी लेने वालों के ऊतकों का मिलान अनिवार्य है। अंग लेने वाला व्यक्ति और देने वाले व्यक्ति के ऊतक अगर मिलेंगे तभी किडनी ट्रांसप्लांट संभव हो सकता है। ऐसा नहीं होने पर दोनों के जान का खतरा हो सकता है। पीएमसीएच में 'टिश्यू टैपिंग' (ऊतक मिलान) करने वाले डॉक्टर भी मौजूद हैं, बावजूद इसके यह सुविधा शुरू नहीं हो पा रही है। आईएमए के डॉक्टर राजीव रंजन प्रसाद कहते हैं किडनी ट्रांसप्लांट के लिए सबसे जरूरी मॉड्यूलर ऑपरेशन थियेटर का निर्माण पीएमसीएच में हो रहा है। जनवरी 2015 तक प्रत्यारोपण शुरू हो सकेगा। अभी इसके लिए यहां काफी काम करना बाकी है। अस्पताल प्रबंधन और सरकार इस दिशा में काम कर रहे हैं। बताते चले कि अस्पताल में किडनी लेने वाले और देने वालों की सूची भी नहीं बनी है। ऐसे में विलंब तो होना ही है।

आई बैंक भी शुरू नहीं

नेत्र विशेषज्ञ डॉ. सुनील कुमार ने बताया कि पीएमसीएच, आईजीआईएमएस और राजेन्द्र नगर अतिविशिष्ट नेत्रालय में नेत्र बैंक हैं लेकिन ये काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि पीएमसीएच में एक बार कार्निया प्रत्यारोपण हो चुका है। नेत्र बैंक में सूचना केंद्र, संग्रह केंद्र और वितरण केंद्र जरूरी हैं पर इन अस्पतालों में ये व्यवस्था ठीक नहीं हैं। कॉर्निया लेने और प्रत्यारोपण के लिए जरूरी है कि मृतक के शरीर से कॉर्निया छह घंटे के अंदर निकाली जाए, पर इसे रखने की सुविधा भी इन आईबैंकों में नहीं है। नेत्र दान के लिए प्रचार-प्रसार भी नहीं हो रहा है।

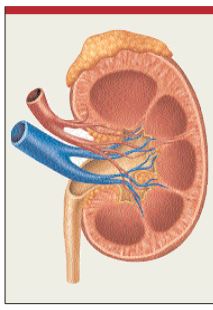

दूसरे राज्य में किडनी दान देंगे 12 लोग

प्रदेश में किडनी प्रत्यारोपण की सुविधा नहीं होने के कारण मंगलवार को सरकार ने 12 लोगों को किडनी दान करने की अनुमति प्रदान की। ये लोग अपने सगे संबंधियों को प्रदेश के बाहर के अस्पतालों में किडनी दान करेंगे। ज्यादातर मरीजों को नई दिल्ली एम्स, मेदांता, एसजीपीजीआई लखनऊ और चंडीगढ़ किडनी प्रत्यारोपण कराना पड़ता है। स्वास्थ्य विभाग के डायरेक्टर इन चीफ की अध्यक्षता में हुई बैठक में इन लोगों को किडनी दान की अनुमति प्रदान की गई।

ट्रेनिंग लेने जाएंगे तीन डॉक्टर

स्वास्थ्य विभाग ने पीएमसीएच और आईजीआईएमएस में किडनी प्रत्यारोपण कराने की सुविधा प्रदान करने की पहल की है। इसी आलोक में पीएमसीएच के तीन डॉक्टर डॉ. दिलीप कुमार, सर्जरी विभाग के डॉ. अशोक कुमार और डॉ. दीपक टंडन एसजीपीजीआई लखनऊ में ट्रेनिंग के लिए जाएंगे। इनमें से एक डॉक्टर तो ट्रेनिंग लेने के लिए रवाना भी हो गए हैं। प्रदेश में हर साल लगभग डेढ़ सौ मरीजों को किडनी प्रत्यारोपण की अनुमति दी जाती है।

जय बिहार

अररिया जिले के फारबिसगंज ब्लॉक के मिरदौल गांव के मूल निवासी हैं अमित कुमार दास

बड़े सपने देखें बिहार के युवा, तय करें लक्ष्य

अमित कुमार दास
संस्थापक व चेयरमैन आईसॉफ्ट साफ्टवेयर ग्रुप सिडनी (शुरुआत दिल्ली से), एमबीआईटी (फारबिसगंज) के संस्थापक

फारबिसगंज जैसे ग्रामीण इलाके में मोती बाबू इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी खोलकर मैं यह बताना चाहता था कि हमारे यहां टैलेंट का अकाल नहीं है, बल्कि युवाओं को प्रोत्साहन देने की जरूरत है। मुझे लगता है कि वर्तमान समय में ज्यादातर छात्र डिग्री के पीछे भाग रहे हैं, जबकि तथ्यात्मक ज्ञान ही उन्हें सफल बना सकता है। मैं युवाओं को शिक्षा के माध्यम से इस लायक बनाना चाहता हूं कि उन्हें तकनीकी क्षेत्र में अवसरों की कोई कमी न हो। नौकरी की तलाश करने के बजाय वे खुद इस लायक बन सकें कि आने वाली पीढ़ियों को रोजगार दे सकें। एमबीआईटी इसी दिशा में एक छोटा सा कदम है। मैं चाहता हूं कि बिहार के गांव के बच्चे बड़े सपने देखें। राह निकलेगी तो दूर तलक जाएगी।

संघर्ष से मिली सफलता

अमित कुमार दास के संघर्षों की कहानी बड़ी दिलचस्प है। उन्होंने इंटर तक की पढ़ाई गांव के ही स्कूल से पूरी की। किसान पिता के लिए ट्रैक्टर खरीदना चाहते थे, लेकिन पैसे नहीं थे। एक मित्र ने सलाह दी दिल्ली की ट्रेन पकड़ो, तभी कुछ हो सकता है। दिल्ली के लिए निकले तो जेब में पैसे कम थे लेकिन कमी नहीं थी तो उम्मीद और उत्साह की। वहां दिल्ली विवि से पत्राचार से बीए किए। बात 1997 की है।

उन्होंने बेसिक कम्प्यूटर लर्निंग कोर्स के लिए एनआईआईटी में आवेदन किया लेकिन दाखिला नहीं मिला, क्योंकि वे काउंसलर द्वारा अंग्रेजी में पूछे गए सवाल (व्हेन डिड यू कम) का जवाब नहीं दे पाए। इसके बाद उन्होंने अंग्रेजी सीखने के लिए क्रैश कोर्स किया। छह माह बाद फिर उसी संस्थान में दाखिला लिए। कोर्स छह माह का था लेकिन वे उसे एक साल में पूरा कर पाए। सन 2000 में अमित फैकल्टी मेंबर के रूप में एनआईआईटी ज्वाइन किए। यह वह प्वाइंट था जहां अमित ने फैसला किया कि वे कम्प्यूटर उद्यमी बनेंगे। फिर शुरू हुई मिस्टर दास और उनके सपनों (साफ्टवेयर डेवलपमेंट) की नई यात्रा, जो दिल्ली के भरत नगर के एक छोटे से कमरे से होते आईसाफ्ट साफ्टवेयर डेवलपमेंट कंपनी के रूप में सिडनी सहित कई देशों तक पहुंच चुकी है।

शहर के रास्ते को गांव की ओर मोड़ दिया

एमबीआईटी में विदेशी अतिथि के साथ अमित कुमार दास।

एक-एक कर सपने पूरे हो रहे थे लेकिन अमित अपने गांव मिरदौल को नहीं भूले। 2009 में लौटे तो गांव और क्षेत्र के लिए मुकम्मल प्लान के साथ। फारबिसगंज में अपने स्वर्गीय पिता के नाम पर मोती बाबू इंटरस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी की स्थापना की। अंतरराष्ट्रीय स्तर के इस कॉलेज में इस वर्ष दिल्ली और राजस्थान तक के छात्रों ने एडमिशन लिया है। अमित गांव में ही एक सुपर स्पेशिएलिटी अस्पताल खोलने वाले हैं। साथ ही गांव वालों को स्वच्छ पेयजल मिले इस योजना पर भी काम कर रहे हैं। उनका कहना है कि दूसरे देशों में बसे बिहार के युवा उद्यमी अपने राज्य में अपना पैसा इंवेस्ट कर रहे हैं। इसे राज्य के विकास के रूप में देखा जा सकता है। बिहारियों को सरकार की आधारभूत संरचना परियोजनाओं में विकास के अवसर नजर आ रहे हैं। वे अपने पैसे को वहीं लगाना चाहते हैं जहां उनका दिल बसा हुआ है। अमित को बिहार अस्मिता सम्मान से भी नवाजा जा चुका है। वह आस्ट्रेलियन बिजनेस काउंसिल के मेंबर व बिहार फाउंडेशन सिडनी के सक्रेटरी भी हैं।